पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

ABRSM

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com,Website : www.abrsm.in

अध्यक्ष	महामंत्री	अतिरिक्त महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
जगदीश प्रसाद सिंघल	शिवानन्द सिंदनकेरा	डॉ. निर्मला यादव	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
09414068780	09343211679	09412169506	09868711893, 09414040403	09415121329

पत्रांक :

दिनांक : 22.8.2019

Press Note

- A delegation of Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh (ABRSM) met Union Human Resource Development Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank in Delhi and submitted charter of demands for various pending problems of education and teachers and demanded early resolution.
- In the meeting which lasted for about 2 hours, the demands of the primary, secondary and higher education wings were presented to the Minister with detailed justification by the Mahasangh.
- Giving information in this regard, Mahasangh President Prof J.P. Singhal said that in the charter of demands, problems like uniform implementation of the seventh pay scale across the country, raising the retirement age of teachers to 65 years, restoring pre-2004 pension scheme, Implementation of time bound promotion scheme at all levels, exempting in-service teachers from PhD course work, counting of past service done in higher education institutions for the sake of promotion, withdrawal the compulsion of PhD Guidance for direct recruitment to the post of Professor and of PhD for career advancement up to the level of Associate Professor, providing minimum financial assistance of 80% of additional financial burden for at least 5 years to enforce the UGC pay scale uniformly across the country, Stopping contract/ad-hoc appointment, regularise and absorb duly selected ad hoc teachers, salary payment of state-aided institution to be made through the Treasury, maintain parity of salary structures, service conditions and retirement benefits of librarians and physical education director with that of regular teachers are chiefly Incorporated.
- Mahasangh General Secretary Shivanand Sindenkera said that various issues have been raised in the demand charter for quality of education by the organization including spending minimum 10% of GDP on education, imposing proper teacher-student ratio in all education institutions, professional training of teachers on regular and systematic basis, preventing commercialization of education, constitute independent autonomous regulatory commissions for school and higher education consisting of academics at the center and state levels, ensure regular and permanent appointment of teachers, suspend the grant and recognition of any institution that has more than 20% faculty positions remaining vacant by the end of the year, ensure Universal unbiased and fair criteria for shortlisting of candidates for the interview for the post of Assistant Professor etc are also included in the memorandum.
- Issues raised by Shaikshik Mahasangh also included recruitment of adequate number of non-teaching supporting staff in educational institutions and freeing teachers from all forms of non-academic work, develop a separate system for mid-day meal, restore autonomy in education, prevent intervention of politics and bureaucracy in education, ensure participation of educationists in all decision making bodies, provide options for study in the mother tongue for every course of education.
- The Human Resource Development Minister understood the topics presented by the Mahasangh one by one in detail and assured to take necessary action soon. In the organization's delegation apart from the president and General secretary, Organization secretary Mahendra Kapoor, Co-organization secretary Ompal Singh, Higher Education wing In-charge Mahendra Kumar, Additional General secretary Dr. Nirmala Yadav, Vice President Dr. Kalpana Pandey, Professor Pragnesh Shah, P. Venkatrao, Secretary Dr. Manoj Sinha, Mohan Purohit, PS Gopakumar, Dr. Geeta Bhatt, joint-secretary Dr. Narayan Lal Gupta, Treasurer Sanjay Raut were present.
- Mahasangh President Prof JP Sinhal said that on the call of the ABRSM, units of all affiliated teacher organizations across the country have sent memorandum to the Prime Minister seeking resolution of the pending problems at the Center.
- It is noteworthy that more than one million teachers of primary to higher education from 25 states across the country have been associated with the ABRSM.

Dr. Sanjay Kumar
Media Incharge
9212794941

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com,Website : www.abrsm.in

अध्यक्ष	महामंत्री	अतिरिक्त महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
जगदीश प्रसाद सिंघल	शिवानन्द सिंदनकेरा	डॉ. निर्मला यादव	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
09414068780	09343211679	09412169506	09868711893, 09414040403	09415121329

पत्रांक :

दिनांक : 22-8-2019

प्रेस विज्ञप्ति

- अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक से भेंट कर शिक्षा एवं शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं का मांगपत्र सौंप कर शीघ्र समाधान की माँग की गई।
- लगभग 2 घंटे तक चली भेंटवार्ता में महासंघ की ओर से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संवर्ग की अलग अलग मांगों को विस्तृत औचित्य के साथ मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के अध्यक्ष प्रो जे पी सिंहल ने बताया कि मांग पत्र में सातवाँ वेतनमान संपूर्ण देश पूर्ण रूप से लागू करने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु देश भर में एकसमान 65 वर्ष करने, 2004 से पूर्व की पेंशन योजना बहाल करने, सभी स्तरों समयबद्ध पदोन्नति योजना लागू करने, सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से छूट देने, उच्च शिक्षा संस्थानों में की गई भूतपूर्व सेवा को पदोन्नति हेतु गिनने, प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएच.डी. गाइडेंस और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर तक कैरियर उन्नति योजना के लिए पीएच.डी. की बाध्यता को वापस लेने, यूजीसी वेतनमान को पूरे देश में समान रूप से लागू करने के लिए राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को कम से कम 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त वित्तीयभार का न्यूनतम 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने, अनुबंध / तदर्थ आधार पर नियुक्तियां रोकने एवं विधिवत चयनित तदर्थ शिक्षकों को अवशोषित और नियमित करने, राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों का भुगतान राजकोष के माध्यम से करने, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षा निदेशकों की वेतन संरचनाओं, सेवाशर्तों और सेवानिवृत्ति लाभों को शिक्षकों के समान करने जैसी मांगे प्रमुखता से शामिल हैं।
- महासंघ के महामंत्री शिवानंद सिन्दनकेरा ने बताया कि संगठन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता हेतु मांगपत्र में विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है इनमें केंद्र द्वारा शिक्षा पर जीडीपी का न्यूनतम 10 प्रतिशत व्यय करने, सभी शिक्षा संस्थानों में शिक्षक छात्र अनुपात लागू करने, शिक्षकों का पेशेवर प्रशिक्षण नियमित और व्यवस्थित आधार पर करने, शिक्षा का व्यावसायीकरण रोकने, स्कूल एवं उच्च शिक्षा के लिए ख्यातनाम शिक्षाविदों से युक्त स्वतंत्र स्वायत्त नियामक आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर गठित करने, शिक्षकों की नियमित और स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित करने एवं किसी संस्था में वर्ष के अंत तक 20 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां होने पर उसके अनुदान और मान्यता को निलंबित करने, सहायक प्रोफेसर के पद पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मानदंड सार्वभौमिक और निष्पक्ष प्रणाली पर आधारित करने जैसे सुझाव मांगपत्र में शामिल किए गए हैं।
- शैक्षिक महासंघ द्वारा मांग की गई है कि शिक्षा संस्थानों में अशैक्षणिक सपोर्टिंग स्टाफ की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करने तथा शिक्षकों को सभी तरह के अशैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने, मिड डे मील की व्यवस्था के लिए पृथक प्रणाली विकसित करने, शिक्षा में स्वायत्तता को बहाल कर राजनीति एवं नौकरशाही के हस्तक्षेप को रोकने तथा शिक्षाविदों की सभी निर्णय लेने वाले निकायों में भागीदारी सुनिश्चित करने, शिक्षा के हर पाठ्यक्रम के लिए मातृभाषा में अध्ययन हेतु विकल्प प्रदान करने जैसे सुझाव महासंघ द्वारा दिए गए हैं।
- महासंघ द्वारा प्रस्तुत विषयों को एक-एक करके विस्तार से मानव संसाधन विकास मंत्री ने समझा और शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही का विश्वास दिलाया। संगठन के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष एवं महामंत्री के अलावा संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह, उच्च शिक्षा संवर्ग प्रभारी महेंद्र कुमार, अतिरिक्त महामंत्री डॉ. निर्मला यादव, उपाध्यक्ष डॉ. कल्पना पांडे, प्रोफेसर प्रग्नेश शाह, पी वेंकटराव, सचिव डॉ. मनोज सिन्हा, मोहन पुरोहित, पी. एस. गोपकुमार, डॉ. गीता भट्ट, सह सचिव डॉ. नारायण लाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष संजय राऊत आदि शामिल थे।
- महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंहल ने बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर देशभर में सभी संबद्ध शिक्षक संगठनों की इकाइयों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर केंद्र स्तर पर लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की गई है।
- उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से देश भर के 25 राज्यों के प्राथमिक से उच्च शिक्षा के दस लाख से अधिक शिक्षक जुड़े हैं।

डॉ. संजय कुमार
मीडिया प्रभारी
9212794941